

प्रेषक,

राधिका झा,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 27 जुलाई, 2017

विषय: अमृत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्वीकृत सैप (SAAP) रू0 247.16 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के साथ राज्यांश अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-854 शा0वि0नि0/02-अमृत-वि0स्वी0/2016 दिनांक 28 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: K-14012/158/ 2015-SC-II, दिनांक 19.06.2017 द्वारा अमृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत सैप(SAAP) ₹247.16 करोड़ के सापेक्ष देय कुल 90 प्रतिशत केन्द्रांश ₹ 222.44 करोड़ में से 20 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹ 44.49 करोड़ एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश की धनराशि ₹ 4.94 करोड़ अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹44.49 करोड़, एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश ₹4.94 करोड़, इस प्रकार कुल ₹49.43 करोड़ (रुपये उन्पचास करोड़ तैतालिस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

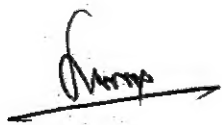
- (i) उक्त धनराशि कुल ₹49.43 करोड़ (रुपये उन्पचास करोड़ तैतालिस लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निगमों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- (iii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- (v) योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।
- (vi) स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदाएं टू-बिड सिस्टम पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाय, ताकि

- सक्षम व अनुभवी फर्मों/निविदादाताओं द्वारा ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जाय तथा उच्च स्तरीय फर्म का चयन किया जा सके।
- (viii) एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (x) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- (xi) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (xii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
- (xiii) स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (xiv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (xv) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र यथासमय शासन को प्रस्तुत किए जायेंगे। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xvi) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में Defect Liability Period तथा अनुस्क्षण की शर्त भी रखी जायेगी
- (xvii) धनराशि का दिनांक 31-3-2018 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13-लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0107-अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र सं0-610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-एलॉटमेंट आईडी0 S.1707/30573



भवदीय,

(राधिका झा)
प्रभारी सचिव।

संख्या-860(1)/IV(2)-श0वि0-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ रुद्रपुर/रुड़की/हल्द्वानी-काठगोदाम।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

